



इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा

संदर्भ: इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर 14 आईपीईएफ भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

- क्षेत्रीय समृद्धि के लिए तीसरी इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक 14 नवंबर, 2023 को सैन फ्रांसिस्को में हुई।
- मई 2022 में शुरू की गई इस रूपरेखा में 14 भागीदार देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है।
- इसे चार स्तंभों में संरचित किया गया है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था।
- भारत स्तंभ II से IV में भाग लेता है, स्तंभ I में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- स्तंभ III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था), IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था), और समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर समझौते के तहत बातचीत में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला जाता है।
- मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान पहले से तय आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ-III); स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और जलवायु-संबंधित परियोजनाओं में निवेश में सहयोग पर केंद्रित है।
- जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और कार्यान्वयन में सहयोग पर जोर दिया गया है।
- निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ-IV) का उद्देश्य वाणिज्य, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी और कर उपायों को बढ़ाना है।
- इसके मुख्य लाभों में सूचना साझा करना, संपत्ति की वसूली और भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए सीमा पार जांच शामिल है।
- **आईपीईएफ:**

- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया, शुरुआत में इसके 12 साझेदार थे, जो सामूहिक रूप से दुनिया की जीडीपी का 40% प्रतिनिधित्व करते थे।
- आईपीईएफ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं है, लेकिन सदस्यों को रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों पर बातचीत करने की अनुमति देता है।
- यह ढांचा चार मुख्य स्तंभों के आसपास संरचित है:

- आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन
- स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचा
- कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी
- निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार।

US Treaty Partner¹

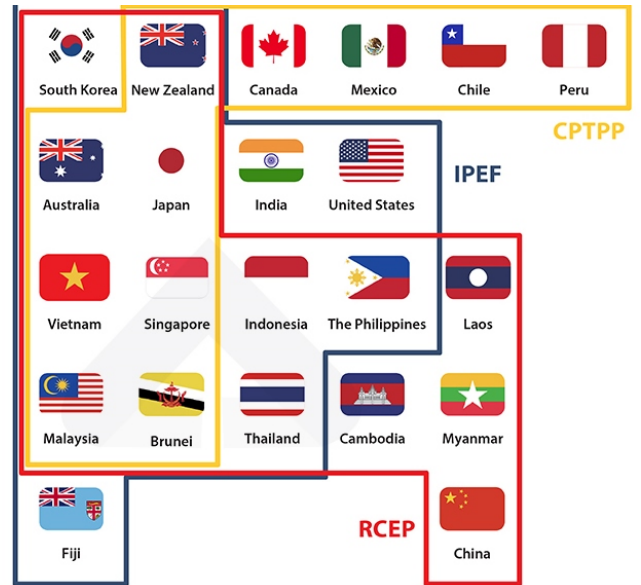
- इसके वर्तमान सदस्यों में भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 देश शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलिया
- ब्रुनेई
- फ़िजी
- भारत
- इंडोनेशिया
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- मलेशिया
- न्यूज़ीलैंड
- फिलिपींस
- सिंगापुर
- थाईलैंड
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- वियतनाम

Quadrilateral Security Dialogue² (Quad)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Other



बिरसा मुंडा

संदर्भ: हाल ही में, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और कई परियोजनाएं शुरू की गईं।

- **जन्म और पृष्ठभूमि:**
 - बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में एक आदिवासी मुंडा परिवार में हुआ था।
 - इस अवधि के दौरान, ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत में जनजातीय जीवन को बाधित कर दिया, जिससे छोटा नागपुर में शोषणकारी जमींदारी प्रणाली शुरू हो गई।
- **ब्रिटिश शासन का प्रभाव:**
 - अंग्रेजों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर आदिवासी कृषि व्यवस्था को बाधित किया और साहूकारों और ठेकेदारों जैसे शोषक तत्वों को शामिल किया।
 - राज द्वारा समर्थित आक्रामक मिशनरी गतिविधियों ने आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में हस्तक्षेप किया।

Face to Face Centres





➤ बिरसा का प्रतिरोध:

- ईसाई धर्म में परिवर्तित, बिरसा ने एक मिशन स्कूल छोड़ दिया जब उन्हें आदिवासियों के धर्मांतरण के ब्रिटिश प्रयासों का पता चला। उन्होंने ब्रिटिश धर्मांतरण के प्रयासों में बाधा डालते हुए 'बिरसैट' मत की स्थापना की।
- सरदारी लाराई आंदोलन के अहिंसक प्रतिरोध के साक्षी बिरसा ने आदिवासी अधिकारों की मांगों को नजरअंदाज होते देखा, जिससे जमींदारों से मजदूरों की संख्या में गिरावट आई।

➤ धार्मिक और सामाजिक सुधार:

- बिरसा ने धार्मिक प्रथाओं में सुधार किया, अंधविश्वासों को हतोत्साहित किया और आदिवासी गौरव को बहाल करने के लिए नए सिद्धांतों और प्रार्थनाओं पर जोर दिया।
- जनजातीय संप्रभुता और भूमि पर पैतृक नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया गया, एक विवाह को बढ़ावा दिया गया।

➤ उलगुलान विद्रोह:

- बिरसा इस समय एक जन नेता बन गए और अनुयायी उन्हें भगवान या धरती आबा मानते थे।
- औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ इन्होंने उलगुलान (महान उपद्रव) का नेतृत्व किया, इस विद्रोह में लोगों से किराया न देने का आग्रह किया और अधिकारियों की चौकियों पर हमला किया।
- इस विद्रोह के दौरान पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों का प्रभावी ढंग से विरोध किया, जिससे उन्हें आदिवासी शोषण को संबोधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

➤ बिरसा की मृत्यु और बिरसा संघर्ष के परिणाम:

- 25 साल की उम्र में ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े गए बिरसा की 9 जून 1900 को कैद में ही मृत्यु हो गई।
- बिरसा के संघर्ष के कारण 1908 का छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम बना, जिसमें आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा की गई और गैर-आदिवासी हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया।

Revolt	Year	Area	Details
Pahariyas' Rebellion	1778	Raj Mahal hills	Led by- martial Pahariyas Against- British expansion on their lands
Chuar Uprising	1776		Led by- Chuar aboriginal tribesmen Against- rise in demands & privation by British
Kol Uprising	1831	Chottanagpur	Leader- Buddho Bhagat Against- expansion of British rule on their lands & transfer of their lands to outsiders Was suppressed
Ho Uprisings	1827 & 1831	Singbhum & Chottanagpur	In 1827- against occupation of Singbhum by British In 1831- against the newly introduced farming revenue policy
Kandh Uprising	1837-56 & 1914	Hilly region from Tamil Nadu to Bengal (1837) & Orissa (1914)	Against- interference in tribal customs & imposition of new taxes
Naikada Movement	1860s	MP & Gujarat	Against- British & caste Hindus
Kharwar Rebellion	1870s	Bihar	Against- Revenue settlement activities
Khonda Dora Campaign	1900	Dabur region in Vishakapatnam	By- Khonda Doras Leader- Korra Mallaya
Bhil Revolts	1817-19 & 1913	Western Ghats	Against Company rule (1817-19) & to form Bhil raj (1913)
Bhuyan & Juang Rebellions	1867 & 1891	Keonjhar (Orissa)	Leaders- Ratna Nayak (1867) & Dharni Dhar Nayak (1891) Against- installation of a British protégé on throne after death of Raja in 1867
Koya Revolts	1880 & 1886	Eastern Godavari region (Andhra Pradesh)	Leaders- Tomma Sora (1880) & Raja Anantayyar (1886) Against- oppression by police, moneylenders; new regulations & denial of their rights over forests
Bastar Revolt	1910	Jagdapur	Against- new feudal & forest levies
Tana Bhagat Movements	1914-15	Chottanagpur	Leaders- Jatra Bhagat, Balram Bhagat Preaching- God's benevolent delegate would arrive to free tribals Against- interference of outsiders Began as Sanskritisation Movement
Rampa Revolts	1916 & 1922-24	Rampa region in Andhra Pradesh	Leader- Alluri Sitaram Raju of the Koyas Against- British interference Raju was captured & killed in 1924
Jharkhand Uprising	1920*	Chottanagpur & parts of Bihar, Orissa, West Bengal	Adivasi Mahasabha was formed in 1937; It was replaced by Regional Jharkhand Party in 1949
Forest Satyagrahas			1- Chenchu tribals (1920s, Guntur district, Andhra Pradesh) 2- Karwars of Palamau (1930s, Bihar) Against- Increasing British control over forests
Gond Uprising	1940s		To bring together believers of Gond Dharma

यूएस चीन जलवायु समझौता

संदर्भ: हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने संयुक्त रूप से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन को बदलने और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौते की घोषणा की।

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन में कटौती के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचे हैं।
- यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और चीन संयुक्त रूप से दुनिया की 38% ग्रीनहाउस गैसों में योगदान करते हैं।

Face to Face Centres





18 November, 2023

- राष्ट्रपति जो बिडेन और शी जिनपिंग ने मुलाकात की, और यह समझौता दो सप्ताह में दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता (COP28) से पहले हुआ।
- यह समझौता वैश्विक जलवायु वार्ता में महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दे सकता है, जिससे अन्य देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध होना आसान हो जाएगा।
- अतीत में अमेरिका और चीन के बीच COP21 तक इसी तरह के सहयोग ने 2015 में पेरिस समझौते की भाषा को प्रभावित किया था।
- COP28 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने, ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जैसे मुद्दों पर बहस चल रही है।
- प्रमुख तेल उत्पादक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने के कारण इस सम्मेलन को जीवाश्म ईंधन के प्रभाव के तहत गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के बारे में चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- अमेरिका-चीन समझौते का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना और कोयला, तेल और गैस उत्पादन से बदलाव में तेजी लाना है।
- इस समझौते में मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, लेकिन देशों की अगली जलवायु प्रतिज्ञाओं में सभी ग्रीनहाउस गैसों को शामिल करने वाले कटौती लक्ष्यों पर जोर दिया गया है।
- एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक मीथेन को संबोधित करने की चीन की प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देती है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह सौदा तेल और गैस उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध नहीं है, और इसमें कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए चीन के वादों का अभाव है।
- चिंताएँ बनी हुई हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया अपर्याप्त रूप से तेज़ और महत्वाकांक्षी है, और अधिक निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
- **यूएनएफसीसी**
 - **यूएनएफसीसीसीसी का परिचय:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसीसी) एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है।
 - **प्राथमिक लक्ष्य:** ग्रीनहाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता को कम करना, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में हानिकारक हस्तक्षेप को रोकना है।
 - **हस्ताक्षर:** 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, जिसे रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
 - **भाग लेने वाले देशों की प्रतिबद्धताएँ:** भाग लेने वाले देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध होना अनिवार्य है।
 - **वार्षिक सम्मेलन:** इस सम्मेलन में 197 पार्टियाँ शामिल हैं, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में प्रगति का आकलन करने के लिए पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) में सालाना बैठक करती हैं।
 - **अनुच्छेद 2 - अंतिम उद्देश्य:** अनुच्छेद 2 कन्वेंशन के अंतिम उद्देश्य को रेखांकित करता है, जिसका लक्ष्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है।
 - **समय सीमा और योग्यताएँ:** पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित करने, खाद्य उत्पादन की सुरक्षा करने और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय सीमा के भीतर उद्देश्य प्राप्त किया जाना चाहिए।
 - **सदस्यों का वर्गीकरण:**
 - **अनुलग्नक I:** 43 पार्टियाँ, मुख्यतः विकसित देश।
 - **अनुलग्नक II:** अनुलग्नक I के 24 देशों से विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - **अनुलग्नक बी:** क्योटो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य वाले अनुलग्नक I देशों का सबसेट।
 - **सबसे कम विकसित देश (एलडीसी):** विशेष दर्जा प्राप्त 47 पार्टियाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में अपनी चुनौतियों को स्वीकार करती हैं।
 - **गैर-अनुलग्नक I:** अनुलग्नक I में सूचीबद्ध नहीं की गई पार्टियाँ, जिनमें मुख्य रूप से कम आय वाले विकासशील देश शामिल हैं।

2022 में हीट एक्सपोज़र

संदर्भ: द लैंसेट के अनुसार, गर्मी के संपर्क में आने से 2022 में भारत में 191 बिलियन संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ है।

मुख्य निष्कर्ष:

- 2022 में, गर्मी के संपर्क में आने से वैश्विक स्तर पर 490 बिलियन संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ, जो 1991-2000 से 42% की वृद्धि दर्शाता है।
- स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन ने व्यावसायिक सूर्य के प्रकाश के जोखिम और कामकाजी उम्र की आबादी के संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों पर विचार करते हुए डेटा संकलित किया है।

भारत पर प्रभाव:

- भारत में 2022 में गर्मी के कारण 191 बिलियन संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ, जो 1991-2000 तक 54% की वृद्धि को दर्शाता है।
- भारत में संबंधित आय हानि 2022 में \$219 बिलियन थी, जो देश की जीडीपी के 6.3% के बराबर है।

कृषि श्रमिकों पर सर्वाधिक प्रभाव:

- कृषि श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतान पड़ा, जिससे 2022 में संभावित घंटों का 64% और संभावित आय का 55% नुकसान हुआ।
- विश्व स्तर पर, कृषि श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि अमेरिका जैसे उच्च आय वाले देशों में निर्माण कार्यों में श्रमिकों का रुझान देखा जा रहा है।

वैश्विक कार्यबल प्रभाव:

- औसतन, दुनिया भर में प्रत्येक श्रमिक ने श्रम क्षमता के 143 संभावित घंटे खो दिए।
- 1.3 बिलियन से अधिक श्रमिकों, जो वैश्विक कार्यबल का 39% हिस्सा हैं, को इस औसत से अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा, जिनमें से 80% निम्न या मध्यम-मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) देशों से थे।

भविष्य के अनुमान:

- आगे अनुकूलन के बिना, 2041-60 की अवधि, 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित तापमान वृद्धि के साथ संगत, 1995-2014 की तुलना में वार्षिक संभावित श्रम घंटों के दोगुने से अधिक नुकसान हो सकता है।
- किसी भी अतिरिक्त शमन प्रयास के परिणामस्वरूप लगभग 2.5 गुना अधिक संभावित श्रम घंटों का नुकसान नहीं हो सकता है।

Face to Face Centres





आर्थिक और वैश्विक असमानताएँ:

- 2010-14 से 2018-22 तक चरम मौसम की घटनाओं से आर्थिक नुकसान 23% बढ़ गया, जो 2022 में कुल 264 बिलियन डॉलर हो गया।
- गर्मी के संपर्क में आने से वैश्विक संभावित आय हानि में \$863 बिलियन का योगदान हुआ।
- निम्न- और मध्यम-एचडीआई वाले देश असंगत रूप से प्रभावित हुए, उनकी आय हानि क्रमशः उनके सकल घरेलू उत्पाद के 6.1% और 3.8% के बराबर थी।

गर्मी से संबंधित बीमारियाँ:

- **हीटस्ट्रोक या सनस्ट्रोक (गंभीर):**
 - लक्षण: गर्म, लाल त्वचा, 105°F (40.5°C) से अधिक बुखार।
 - विशेषताएँ: 50% से अधिक प्रभावित बच्चों को पसीना नहीं आता।
 - गंभीरता: यह भ्रम, कोमा या सदमे का कारण बन सकता है।
 - शीघ्र उपचार: तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपचारित मामलों में मृत्यु दर अधिक होती है।
- **गर्मी से थकावट:**
 - लक्षण: पीली त्वचा, अत्यधिक पसीना, मतली, चक्कर आना, बेहोशी या कमजोरी।
 - बुखार: 100 - 102°F (37.8 - 39°C) के बीच हल्का बुखार अस्थायी रूप से हो सकता है।
 - निर्जलीकरण लिंक: अक्सर अत्यधिक पसीने के कारण निर्जलीकरण को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
 - प्रगति जोखिम: गंभीर मामले हीटस्ट्रोक तक बढ़ सकते हैं, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
 - प्रबंधन: हल्के लक्षणों को घर पर ठीक किया जा सकता है; लगातार या बिगड़ते लक्षणों के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
- **गर्मी से अकड़न (Heat Cramp):**
 - विशेषताएँ: पैरों (पिंडली या जांघ की मांसपेशियों) और पेट में तीव्र मांसपेशियों में ऐंठन; कोई बुखार नहीं।
 - अन्य लक्षण: हाथों में जकड़न या ऐंठन भी हो सकती है।
 - समाधान: आमतौर पर पर्याप्त तरल पदार्थ के सेवन और ठंडक के बाद लक्षणों में सुधार होता है।
 - अवधि: सभी लक्षण कुछ घंटों के भीतर कम हो जाने चाहिए।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

जनजातीय सलाहकार परिषद



जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिश के बाद, ओडिशा सरकार ने हाल ही में जनजातीय समुदायों को शिक्षा और उद्योग के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में:

- भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत, जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) को अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में अनिवार्य किया गया है और, यदि निर्देश दिया जाए, तो अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों में जिसमें कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है में भी इसका गठन किया जाता है।
- जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) का गठन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि जैसे अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में किया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे बिना अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में भी किया गया है।
- यह सलाहकार निकाय राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है।

पांचवीं अनुसूची में भूमिका:

- भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची मुख्य रूप से आदिवासी समूहों द्वारा बसाए गए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन और शासन को नियंत्रित करती है।
- अनुच्छेद 244(1): पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं।
- भारत के राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या किसी निर्दिष्ट हिस्से को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है।
- राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर सकते हैं।

क्रायोस्फ़ियर



हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया को क्रायोस्फीयर की रक्षा के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की जरूरत है।

क्रायोस्फीयर के बारे में:

- क्रायोस्फीयर विभिन्न रूपों में पृथ्वी के जमे हुए पानी को संदर्भित करता है जैसे कि बर्फ की चादरें, नदी की बर्फ, ग्लेशियर, फर्माफ्रॉस्ट, समुद्री बर्फ और ठोस वर्षा आदि। यह ग्रह की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह पृथ्वी का 68% से अधिक ताज़ा पानी बर्फ और ग्लेशियरों में रखता है, जबकि अन्य 30% भूमिगत है।
- यह तापमान परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, क्रायोस्फीयर में वैश्विक स्तर पर तीव्र कमी आ रही है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा शुरू किए गए "क्रायोस्फीयर और जलवायु" जैसे कार्यक्रमों ने अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तनशीलता के बारे में हमारे ज्ञान को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

Face to Face Centres





<p style="text-align: center;">खसरा</p> 	<p>हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2021-2022 के बीच खसरे से संबंधित मौतों में लगभग 43% की वृद्धि दर्ज की है।</p> <p>खसरे (Measles) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ खसरा एक वायुजनित रोग है जो पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से सीधे संपर्क और श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। ➤ यह शुरू में पूरे शरीर में फैलने से पहले श्वसन पथ को प्रभावित करता है और गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है। ➤ जो लोग प्रतिरक्षित नहीं हैं, जैसे बिना टीकाकरण वाले लोग या बिना प्रतिरक्षा प्राप्त किए टीका लगाए गए लोगों के बीमार होने की संभावना अधिक होती है। ➤ विशेष रूप से, बिना टीके वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खसरा होने पर गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। ➤ लक्षण: खसरा होने के लगभग 10-14 दिनों के बाद अक्सर तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल आंखें और गालों के अंदर सफेद धब्बे होते हैं। ➤ उपचार: खसरे के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है, जो टीकाकरण के माध्यम से रोकथाम की गंभीरता पर जोर देता है। ➤ पहल: खसरा और रूबेला पहल (एम एंड आरआई) अमेरिकन रेड क्रॉस, सीडीसी, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसे समूहों का एक टीम प्रयास है। ➤ वे दुनिया भर में कई स्थानों पर खसरा और रूबेला से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
<p style="text-align: center;">गामा-किरण विस्फोट</p> 	<p>एक हालिया अध्ययन में प्रस्तावित किया गया है कि गामा-रे बस्टर्स (जीआरबी) में ओजोन परत को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने की शक्ति हो सकती है।</p> <p>गामा-किरण विस्फोट (गामा-रे बस्टर्स) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ गामा-किरण विस्फोट (जीआरबी) गामा-किरण प्रकाश की अल्पकालिक चमक हैं, जो हमारे सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवन में उत्सर्जित ऊर्जा की तुलना में कुछ सेकंड में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। ➤ उनके दो चरण होते हैं: गामा-किरणों का प्रारंभिक विस्फोट (शीघ्र उत्सर्जन) और उसके बाद लंबे समय तक चलने वाली बहु-तरंगदैर्घ्य, जो विस्फोट के बाद की चमक है। ➤ जब न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो छोटे विस्फोट होने की संभावना होती है, जबकि बड़े तारों के ब्लैक होल में गिरने पर दीर्घ विस्फोट होते हैं। ➤ जब कोई गामा-किरण विस्फोट (जीआरबी) होता है, तो यह अवलोकनीय ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय गामा-रे फोटॉन का सबसे चमकीला स्रोत बन जाता है। ➤ विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ➤ वे अविश्वसनीय रूप से गर्म और ऊर्जावान खगोलीय पिंडों जैसे न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा और ब्लैक होल के आसपास निर्मित होते हैं।
<p style="text-align: center;">समाचारों में स्थान</p> <p style="text-align: center;">सोमालिया</p>	<p>हाल ही में, सोमालिया में भयंकर बाढ़ आई, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया।</p> <p>सोमालिया (राजधानी: मोगादिशु)</p> <p>अवस्थिति : सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है, विशेष रूप से उस क्षेत्र में जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है।</p> <p>राजनीतिक सीमाएँ: सोमालिया की सीमाएँ पश्चिम में इथियोपिया, उत्तर-पश्चिम में जिबूती, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण-पश्चिम में केन्या से लगती हैं।</p> <p>भौतिक विशेषताएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ उत्तर में ओगो पर्वत इलाके को आकार देते हैं, जो अदन की खाड़ी के तट के साथ पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। ➤ सोमालिया की अफ्रीका में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है, जो हिंद महासागर और अदन की खाड़ी के साथ 3,333 किलोमीटर तक फैली हुई है। ➤ सोमालिया सोमाली सागर द्वारा सेशेल्स से अलग होता है। 

POINTS TO PONDER

- ❖ किस पहल के तहत योगिनी चामुंडा और गोमुखी मूर्तियों को यूनाइटेड किंगडम से भारत वापस लाया गया था? - **इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट**
- ❖ उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पास निर्माणाधीन सुरंग में बचाव अभियान के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा किस प्रकार के विमान का उपयोग किया गया था? - **C130J सुपर हरक्यूलिस**
- ❖ हाल ही में मालदीव गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? - **मोहम्मद मुइज्जु**
- ❖ हाल ही में किस देश ने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक -प्लस (ADMM-Plus) में आतंकवाद-निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता करने का प्रस्ताव दिया है? - **भारत**
- ❖ भारत में अफ्रीम पोस्ट से उत्पादित दो प्रकार के मादक कच्चे माल कौन से हैं? - **अफीम गॉद (लेटेक्स) और पोस्ता भूसे का सांद्रण (सीपीएस)**

Face to Face Centres

